

श्रम विभाग

दिनांक 2 जनवरी, 1985

सं. ओ.वि./हिसार/57-84/177.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा, (2) हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा, के श्रमिक श्री सीता राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री सीता राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./यमुना/299-83/184.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि निदेशक, स्थानीय प्रशासन हरियाणा, चंडीगढ़ (2) नगरपालिका, जगाधरी, के श्रमिक श्री नवाब सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री नवाब सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./हिसार/65-84/191.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा (2) हरियाणा राज्य परिवहन हिसार, के श्रमिक श्री राजपाल परि. नं० 90 तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./हिसार/53-84/198.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा (2) हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा, के श्रमिक श्री उदम सिंह परि. 27 तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री उदम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि./पत्नी/46-84/205.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ (2) कार्यकारी अभियन्ता, सिविल वर्क्स डिविजन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, अम्बाला शहर (3) सुप्रीटेन्डिंग इंजीनियर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, दुआ बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री लक्ष्मी चन्द चौकीदार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-अम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री लक्ष्मी चन्द चौकीदार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

जे० पी० रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
अम विभाग।

The 12th December, 1984

No. 9/5/84-6Lab/8786.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding Officer, Labour Court, Rohtak, in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Mathru Wood Works Nahra Nehri Road, Bahadurgarh :—

BEFORE SHRI B. P. JINDAL, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, ROHTAK

Reference No. 136 of 83

between

SHRI UMED SINGH, WORKMAN AND THE MANAGEMENT OF M/S MATHRU WOOD WORKS, NAHRA NEHRI ROAD, BAHADURGARH

Present:—

None for the parties.

AWARD

1. In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana, referred the following dispute between the workman Shri Umed Singh and the management of M/s. Mathru Wood Works, Nahra Nehri Road, Bahadurgarh, to this Court, for adjudication.—vide Labour Department Gazette Notification No. ID/RTK/71-83/45358-63, dated 5th September, 1983 :—

Whether the termination of service of Shri Umed Singh was justified and in order? If not, to what relief is he entitled?

2. After receipt of the order of reference, notices were issued to the parties. The workman appeared but later on absented. The service upon the management could not be effected. The case of workman is that he was in the employment of the respondent since 1st June, 1980 as a Chowkidar and that his services were terminated unlawfully by the respondent on 16th September, 1982 in complete disregard of the provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

3. As already observed the workman appeared through Shri Dhan Singh his Authorised Representative but later on absented. So, it seems that the workman is not interested in prosecution of the reference. So, the same was ordered to be dismissed and answered accordingly. There is no order as to costs.
Dated the 20th November, 1984.

B. P. JINDAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Rohtak,
Camp Court, Bahadurgarh.

Endorsement No. 136-83/3694, dated 26th November 1984.

Forwarded (four copies) to the Secretary to Government, Haryana Labour and Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. P. JINDAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Rohtak,
Camp Court, Bahadurgarh..

No. 9/5/84-6Lab/8787.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding Officer, Labour Court, Rohtak in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Matharu Wood Works, Nahara Nohari Road, Bahadurgarh :—

BEFORE SHRI B. P. JINDAL, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, ROHTAK

Reference No. 138 of 83

between

SHRI JAI NARAIN, WORKMAN AND THE MANAGEMENT OF M/S MATHARU WOOD WORKS, NAHARA NOHARI ROAD, BAHADURGARH

Present :—

None for the parties.

AWARD

1. In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana, referred the following dispute between the workman Shri Jai Narain and the management of M/s Matharu Wood Works, Nahara Nohari Road, Bahadurgarh, to this Court, for adjudication,—vide Labour Department Gazette Notification No. ID/RTK/70/83/45698-703, dated 6th September, 1983 :—

Whether the termination of services of Shri Jai Narain, was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

2. After receipt of the order of reference, notices were issued to the parties. The workman appeared but later on absented. The service upon the management could not be effected. The case of the workman is that he was in the employment of the respondent since 1st June, 1980 as a helper and that his services were terminated unlawfully by the respondent on 19th November, 1982 in complete disregard of the provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

3. As already observed the workman appeared through Shri Dhan Singh his Authorised Representative but later on absented. So, it seems that the workman is not interested in prosecution of the reference. So, the same was ordered to be dismissed and answered accordingly. There is no order as to costs.

Dated, the 20th November, 1984.

B. P. JINDAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Rohtak,
Camp Court, Bahadurgarh.

Endorsement No. 138-83/3695, dated 26th November, 1984.

Forwarded (four copies) to the Secretary to Government, Haryana Labour and Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. P. JINDAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Rohtak,
Camp Court, Bahadurgarh.

M. SETH
Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.